in different sectors there was improvement in the growth-rate ol the economy, buoyancy in public revenues an, d} decline in the rate of inflation.

बंजर भूमि क्षेत्र

2221. डा० रत्नाकर पांडेय : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसी कुल कितनी बंजर भूमि है, जिसका खेती के लिए और वन रोपण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता ;

(ख) उसमें से कितनी भूमि में वन लगाये जाने का विचार है ;

(ग) वन रोपण की सम्पूर्ण योजना को कितने चरणों में पूरा किया जायेगा ; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की कुल कितनी बंजर भमि का उपयोग किए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : (क) राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वार किए गए एक आकलन के अनुसार देश में गैर-वन और अवक्रमित वन क्षेत्र लगभग 175 मिलियन हेक्टेयर है ।

(ख) और (ग) अगले कुछ वर्षों में कुल वनरोपण कार्यक्रम निम्नानुसार होने की उम्मीद है :—

वर्ष	मिलियन हेक्टेयर
1986–87 . .	1.7
1987–88 . .	2.3
1988–89 . .	3.0
1989–90 . .	4.0
1990–91 . .	5.0

(घ) वन रोपण के लिए परती भूमि का निर्धारण साल-दर साल आधार पर किया जाता है ।

हिन्दी समाचार समितियों का बन्द किया जाना

2222. डा० र लाकर पांडेय : क्या **सूचना और प्रस.रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी की दोनों समाचार समितियां हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती या तो बंद कर दी गयी है अथवा बंद प्राय: हो गयी है ;

(ख) क्या अहिन्दी राज्यों में काम कर रही इन समितियों ने राजभाषा विभाग से कोई सहायता मांगी थी ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया ; और

(घ) क्या सरकार ऐसी किसी संस्था को सहायता प्रदान करेगी, जो हिन्दी अथवा अन्य किन्हीं भारतीय भाषाओं में समाचार वितरित करेगी ?

सूचना और प्रसारण मत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) देश में समाचार एजेंसियां निजी स्वामित्व में हैं और सरकार प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप इनके आन्तरिक कार्य संचालन में हस्तक्षेप नहीं करती । इसलिए सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या हिन्दी की प्रश्नास्पद दो समाचार एजन्सियां वास्तव में कार्य कर रही हैं । तथापि, समाचार पत्र उद्योग में यह व्यापक धारणा है कि ये दोनों एजेंसियां, अपनी बिगड़ी आर्थिक स्थिति के कारण, वास्तव में ठप हो गई हैं ।

(ख) और (ग) राजभाषा विभाग को हिन्दुस्तान समाचार से आर्थिक सहायता के लिए एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था । इसे स्वीकार नहीं किया जा सका, क्योंकि इस विभाग की इस प्रकार की सहायता देने की कोई स्कीम नहीं है ।

(घ) जी, नहीं ।